दैनिक जागरण

पहले कार्य की योजना बनाएं और फिर योजना अनुरूप कार्य करें

दिशाहीन कांग्रेस

लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद जब यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस अपनी रीति-नीति में व्यापक बदलाव लाएगी तब वह दिशाहीनता से ग्रस्त दिख रही है। किसी को नहीं पता कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की जो पेशकश की थी उसका क्या हुआ? इस बारे में भी कोई खबर नहीं कि एक और करारी हार पर कोई आत्ममंथन किया जा रहा है या नहीं? चूंकि यह पता नहीं कि कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर क्या हो रहा है इसलिए इस पर हैरानी नहीं कि राज्यों में भी उठापटक तेज होती दिख रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायक सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति में शामिल होने को तैयार हैं। पता नहीं कांग्रेस से मुक्त होने को तैयार इन विधायकों की यह इच्छा पूरी होगी या नहीं कि राज्य कांग्रेस का विलय तेलंगाना राष्ट्र समिति में हो जाए, लेकिन अगर वे पार्टी छोड़ देते हैं तो एक और राज्य में कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई देगी। कांग्रेस के लिए यह भी शुभ संकेत नहीं कि पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके बड़बोले मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। यदि यह तनातनी और अधिक बढ़ी तो इसका असर कांग्रेस की एकजुटता और साथ ही उसकी छवि पर भी पड़ेगा। पार्टी नेतृत्व को इसकी चिंता करनी चाहिए कि पंजाब में कांग्रेस आपसी कलह का शिकार न होने पाए।

कांग्रेस नेतृत्व को यह समझना होगा कि अगर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के रुख-रवैये से नाखुश हैं तो इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। नवजोत सिंह सिद्धू एक अर्से से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अमरिंदर सिंह की परवाह नहीं है। भले ही नवजोत सिंह यह कह रहे हों कि उन्हें हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन सच यही है कि वह खुद मुख्यमंत्री को यथोचित महत्व देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए है? सच्चाई जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब के साथ-साथ अन्य अनेक राज्यों में भी कांग्रेस गुटबाजी और दिशाहीनता से ग्रस्त है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। जैसे यह नहीं पता कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं वैसे ही इस बारे में भी संशय ही अधिक है कि विभिन्न राज्यों के पार्टी अध्यक्ष अपने-अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं? सबसे खराब बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जैसे लोकसभा चुनावों में पराजय के लिए उसके अलावा अन्य सब जिम्मेदार हैं। कहीं राज्यों के नेतृत्व पर दोष मढ़ा जा रहा है तो कहीं सहयोगी दलों पर। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीति कराई जा रही है कि भाजपा गलत तौर-तरीके अपनाकर चुनाव जीत गई। इस सबसे तो यही लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व हार के मूल कारणों से जानबूझकर मुंह मोड़ रहा है। ऐसा करना मुसीबत मोल लेना ही है।

सिक्योर हिमालय

चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में चल रही सिक्योर हिमालय परियोजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की उत्तरकाशी के डीएम की पहल सराहनीय मानी जा सकती है। इससे जहां इस क्षेत्र के निवासियों के हितों के संरक्षण में मदद मिलेगी, वहीं आजीविका के साधन भी विकसित होंगे। जाहिर है कि इससे स्थानीय निवासियों की आर्थिकी संवरने के साथ ही उनके जीवनस्तर में सुधार आएगा। साथ ही वे हिमालयी क्षेत्र में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में सक्रिय रूप से भागीदारी भी करेंगे। फिर वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ ही आजीविका विकास सिक्योर हिमालय परियोजना का अहम हिस्सा भी है। बता दें कि उत्तराखंड सहित देश के चार हिमालयी राज्यों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से दो अक्टूबर, 2017 से इस परियोजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एवं गोविंद वन्यजीव विहार से लेकर अस्कोट अभयारण्य तक के उच्च हिमालयी क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 60 गांव भी हैं, जिनमें गोविंद वन्यजीव विहार में आने वाले 43 और अस्कोट अभयारण्य के 17 गांव शामिल हैं। इन गांवों के बाशिंदे भी राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति वन कानूनों की बंदिशों से जूझ रहे हैं। ऐसे में सिक्योर हिमालय परियोजना के शुरू होने से वहां के निवासियों की उम्मीदें परवान चढ़ी हैं। असल में परियोजना के अंतर्गत इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जैवविविधता के साथ ही हिम तेंदुओं के संरक्षण के अलावा स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका विकास को प्रभावी कदम उठाए जाने हैं। इसके लिए एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गंगोत्री से लेकर अस्कोट तक के संरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में आजीविका विकास के तहत ईको टूरिज्म, जड़ी-बूटी और फलोत्पादन, रोजगारपरक प्रशिक्षण, चारा विकास से संबंधित कार्यक्रम विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किए जाएंगे। ऐसे में यह आवश्यक है कि स्थानीय निवासियों को केंद्र में रखकर आजीविका विकास के कार्यक्रम तय किए जाएं। इसके लिए वहां के लोगों विशेषकर महिलाओं से सुझाव और जानकारियां ली जानी आवश्यक हैं कि वे क्या चाहते हैं। वजह ये कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ही पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं।

शुरुआती सौ दिनों का एजेंडा

जीएन वाजपेयी

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कामकाज की शुरुआती सफलता ही मंत्रियों के उनके पदों पर बने रहने का पैमाना बनाई जानी चाहिए

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई मंत्रिपरिषद के गठन के बाद से तमाम जानकार मोदी सरकार को सलाह देने में लगे हुए हैं। एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं भी सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि शुरुआती सौ दिनों के लिए उसका एजेंडा क्या होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत स्पष्ट रूप से झलकते हैं। रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। मांग के मोर्चे पर भी फिसलन है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से वैश्विक अनिश्चितता, मंदी और मुश्किल हालात पैदा होंगे। पहले कार्यकाल में मोदी ने जीएसटी, आइबीसी, रेरा और एमपीसी जैसे कुछ एकल सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था। दूसरे कार्यकाल में मोदी को श्रम और भूमि सुधारों जैसे उन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो और भारतीय अर्थव्यवस्था को दहाई अंकों वाली जीडीपी वृद्धि के दौर में दाखिल किया जा सके। शुरुआती सौ दिनों का समग्र एजेंडा मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को मंदी की जकड़न से बाहर निकालने पर केंद्रित होना चाहिए।

अर्थव्यवस्था के तीन भाग होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि, द्वितीयक में विनिर्माण और तृतीयक में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। भारत में विनिर्माण और सेवा से जुड़े बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, उद्योग और यहां तक कि रेल और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों की गिनती भी आर्थिक मंत्रालयों में की जाती है।

जीडीपी में कृषि का योगदान भले ही 15.7 प्रतिशत हो, लेकिन देश में रोजगार के 60 प्रतिशत साधन और तकरीबन 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसके बावजूद न तो इसे आर्थिक मंत्रालय का दर्जा दिया जाता है और न ही इसे खास तवज्जो दी जाती है। एक को छोड़कर किसी भी आर्थिक अखबार ने नवनियुक्त कृषि मंत्री का प्रोफाइल भी प्रकाशित नहीं किया। कृषि अर्थव्यवस्था की सुस्ती और ग्रामीण क्षेत्र में बदहाली स्पष्ट रूप से झलक रही है और इससे समग्र मांग बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नई सरकार कृषि अर्थव्यवस्था की अनदेखी करने का जोखिम नहीं ले सकती। यदि उसने इसे नजरअंदाज किया तो ग्रामीण बाजार के हालात और खराब होकर अर्थव्यवस्था की तस्वीर और बिगाड़ेंगे। कृषि मंत्रालय को भी आर्थिक मंत्रालय का दर्जा दिया जाना चाहिए और उसके विचारों, सुझावों और प्रस्तावों को भी अन्य आर्थिक मंत्रालयों जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीसीईए में शामिल कर एकदम सही किया। माना जा रहा है कि पिछली सरकार में राधामोहन सिंह अपने काम से कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने तोमर को कृषि मंत्री बनाया है। ऐसे में नए मंत्री को भी वैसे ही सक्रिय हो जाना चाहिए जैसे त्वरित प्रभाव डालने के लिए वित्त मंत्री को सक्रिय होना होता है। कृषि मंत्रालय की समीक्षा भी पूरी सतर्कता के साथ निरंतर की जानी चाहिए।

बीते चार वर्षों से कंस्ट्रक्शन उद्योग कुछ ठहराव का शिकार रहा है। इसके लिए जीएसटी और रेरा जैसे सुधार भी कुछ जिम्मेदार रहे हैं। इस उद्योग का तुरंत कायाकल्प करना होगा। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। इस क्षेत्र को मदद पहुंचाने के लिए किफायती आवास योजना को अतिरिक्त सहारा दिया जाना चाहिए। आवासीय कंपनियों सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। कंस्ट्रक्शन उद्योग करीब 150 से अधिक अन्य उद्योगों को प्रभावित करता है और कृषि क्षेत्र के साथ मिलकर यह रोजगार सृजन के मामले में बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। सड़क, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डे और अस्पताल इत्यादि के रूप में विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास को और अधिक रफ्तार दी जानी चाहिए। इससे कई खस्ताहाल क्षेत्रों के हालात सुधरेंगे और नई नौकरियों के तमाम अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र को जोड़ने के प्रयास करने होंगे। बीते पांच वर्षों से इसका बीड़ा अकेले सरकार ने ही उठा रखा है।

अगले पांच वर्षों के दौरान भारत को बुनियादी ढांचे में दस लाख करोड़ डॉलर से अधिक के निवेश की दरकार है। इसकी पूर्ति सरकारी खर्च से होना असंभव है। बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के मामले में एक सख्त समयसीमा निर्धारित करना अनिवार्य होगा ताकि उनके क्रियान्वयन में देरी की गुंजाइश न रहे। परियोजनाओं में देरी पर दंडित करने और समय से पहले पूरी करने पर पुरस्कृत करने की व्यवस्था बनानी होगी।

हालांकि 2014 के चुनाव के बाद निजी निवेश में तेजी आई थी, मगर शुरुआती तेजी के बाद तमाम कारणों के चलते उसमें गतिरोध आ गया। शिथिल पड़े उद्योगपतियों में गर्मजोशी का भाव भरा जाना चाहिए। जब तक उनके भरोसे में बहाली नहीं होती और निजी निवेश रफ्तार नहीं पकड़ता तब तक सरकार को अपने खर्च से वृद्धि को गति देना जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही अब समय आ गया है कि भारत राजकोषीय घाटे के बजाय संरचनागत ढांचे पर ध्यान केंद्रित करे। यह अधिक स्थायित्व वाली व्यवस्था होगी। साथ ही वित्त मंत्री को संसाधन जुटाने के मसले का भी समाधान तलाशना होगा। जीएसटी की कमियों को दूर करना और आसान एवं सरल प्रत्यक्ष कर संहिता भी सौ दिनों के एजेंडे में शामिल होनी चाहिए। शुरुआती सौ दिनों में नकदी और तरलता की स्थिति बेहतर बनाने पर भी काम करना होगा। आइएलएंडएफ संकट के बाद से खासकर एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और यहां तक कि सामान्य कंपनियों के लिए तरलता का संकट पैदा हो गया है। उधारी में भारी कमी आई है। आरबीआइ ने जरूर कुछ कदम उठाए हैं जिससे कुछ तात्कालिक राहत मिली है। हालांकि मध्यम और दीर्घावधिक उपायों के अभाव में इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकारी बैंकों के बहीखातों में सुधार दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन इसे युद्ध स्तर अंजाम देना होगा। फिलहाल महंगाई मुंह नहीं फैला रही है और काबू में है। इससे रिजर्व बैंक को वास्तविक ब्याज दरें 2.5 प्रतिशत तक कम करनी चाहिए। वर्ष 2003-04 में जब भारत की जीडीपी वृद्धि नौ प्रतिशत के आसपास थी तब आवासीय ऋण पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत थी और कारोबारियों को भी 7.5 से 7.75 प्रतिशत की दर पर कर्ज मिल रहा था।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध से भारत के लिए बने अवसरों को भुनाने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को तेजी से प्रयास करने चाहिए। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों का भी तोड़ निकालना होगा। अवसरों की यह खिड़की हमेशा नहीं खुली रहेगी। गोयल काबिल मंत्री रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक कुशल राजनयिक वाली भूमिका भी निभानी होगी। राज्य मंत्री के रूप में हरदीप पुरी उनके बहुत काम आएंगे।

सौ दिवसीय एजेंडे की सफलता ही मंत्रियों के उनके पदों पर बने रहने का पैमाना बनाई जानी चाहिए। खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। व्याकुल भारत ने मोदी में भारी भरोसा दिखाया है और उसे उम्मीद है कि मोदी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सौ दिनों का प्रदर्शन इस भरोसे पर खरा उतरना चाहिए।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

राजनीतिक सबक सिखाने वाले नतीजे

मालिनी अवस्थी

राजनीति गणित नहीं, बल्कि केमिस्ट्री होती है, इसे उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित करके दिखाया

लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद से ही इस पर हैरानी जताई जा रही है कि आखिर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सामाजिक केमिस्ट्री के आगे जातीय अंकगणित कामयाबी क्यों नहीं हो सका? इस सवाल का जवाब देने के लिए दो प्रसंगों का उल्लेख आवश्यक है। पहला, गोरखपुर से आगे महाराजगंज का है। एक कार्यक्रम के लिए मैं वहां गई थी। वहां ग्रामीण महिलाओं की हालत पर बात चल निकली तो 20-22 बरस की एक युवती कहने लगी, 'दीदी, मोदी जी घर-घर शौचालय बनवाइन हैं। पहले तो सब हंसत रहे, लेकिन ई समझ ल्यो ई बहुत बड़ा काम हुआ है।' उसका आदमी रामाधीन भी बोल उठा, 'हमारे गांव में अब एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां शौचालय न बना हो। एक आदमी ने शौचालय की जगह कमरा बनवा लिया तो हमारे गांव प्रधान ने मोबाइल से फोटो खींच कर मोदी जी से शिकायत करने की धमकी दे डाली।' यह सुनकर उसकी पत्नी बड़े आत्मसंतोष के साथ बोली, 'चार दिन में उई पड़ोसी ठीक हुई गे, शौचालय बन गइल।' फिर उत्सुकता से पूछने लगी, 'दीदी जीत त जइहें न मोदी जी?' ऐसे तमाम अनुभवों से मेरा सामना हुआ।

दूसरा प्रसंग लखनऊ से बलिया जाते समय ड्राइवर आबिद से चुनावी चर्चा का है। आबिद से बातचीत के दौरान एक रोचक तथ्य उजागर हुआ। आबिद बोला, 'मैडम, हमारी अम्मी ने हमारे अब्बू की ही बात नहीं मानी और मोदी को वोट डाल आई हैं। इस पर मैंने पूछा-आबिद, मोदी को वोट क्यों दिया अम्मी ने? अब आबिद नहीं, एक भावुक बेटा बोल रहा था-कहने लगा-'जबसे हमने होश संभाला, अम्मी को घर में खटते ही देखा। हमारी अम्मी को पहली बार सोने के लिए छत नसीब हुई। अम्मी कहती हैं, 'अपना घर भी होगा, ऐसा सोचना बंद कर दिया था, तो जिसने हमारे लिए किया, उसका हक अदा करना ही चाहिए।'

इन दो प्रसंगों में उत्तर प्रदेश और शायद देश के भी वोटर के मन की थाह छिपी है, लेकिन यह बात दिल्ली का बुद्धिजीवी और वहां का मीडिया नहीं समझ पा रहा था। शौचालय निर्माण पर हंसने वाला बुद्धिजीवी जमीन से इतना कटा हुआ था कि वह समझ ही नहीं सका कि घर में बना शौचालय, एक स्त्री के लिए सुरक्षा और आत्मसम्मान का कितना बड़ा संबल बन चुका था! दिल्ली के बड़े-बड़े पत्रकार मानने को ही तैयार नहीं होते थे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सामने भाजपा खड़ी भी हो सकेगी। उन्हें लगता था कि सपा-बसपा मिलकर भाजपा को बीस सीटों पर रोक लेंगे। दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार सब यही मानते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत को जोड़ने से भाजपा का सफाया हो जाएगा। वे भूल गए कि राजनीति गणित नहीं होती है, राजनीति केमिस्ट्री होती है और जिसे प्रदेश की जनता ने फिर साबित किया।

मुझे लोगों से मिलते और उनको सुनते हुए एक लंबा समय गुजर गया। लोक में भ्रमण करने के दौरान खेत-खलिहान, घर-आंगन से लेकर चाय-पान की गुमटी की चर्चाएं मेरे कान में पड़ती हैं। इस दौरान मैं उनका मन पढ़ने की कोशिश करती हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम को लेकर मुझे कभी कोई शंका नहीं थी। मैं देख रही थी कि गठबंधन की मजबूती के दावे मीडिया में चल रहे हैं, जबकि जनता तो उसका नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मुझे नतीजे अलग दिख रहे थे। दूरस्थ गांवों में पहुंची बिजली और बुनियादी सुविधाओं का असर भी बोल रहा था। पहली बार गरीबों को अपना घर नसीब हुआ था। उनके अपने बैंक खाते खुल गए थे जिनमें बिना किसी बिचौलिए के सीधे धनराशि पहुंच रही थी। घर-घर बने शौचालयों और उज्ज्वला गैस योजना ने महिलाओं को एक बेहतर जीवनशैली प्रदान की थी। गरीब आदमी के लिए इलाज बेहद खर्चीला होता है। इलाज का भारी-भरकम खर्च किसी भी आम आदमी की जैसे जान निकाल लेता है। इसलिए ग्रामीण जनता को जब पहली बार आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से सस्ता इलाज मुहैया होने लगा तो लोग मोदी सरकार के प्रति कृतज्ञता से भर उठे। ऐसा नहीं कि आम आदमी के लिए योजनाएं पहले नहीं बनीं, लेकिन बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के इतनी ईमानदारी से क्रियान्वित अवश्य पहली बार हुईं। यही ईमानदारी लोगों के दिलों में घर कर गई।

आम तौर पर देखा गया है कि ग्रामीण वोटर सांसद के चुनाव में उदासीन रहता है। वोटर वह उत्साह नहीं दिखाता जो अमूमन ग्राम प्रधान या विधायक के चुनाव में दिखता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गांव, खेत, घर-आंगन तक मोदी के व्यक्तित्व का जादू ऐसा चढ़ा कि वोटर ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान किया। भाजपा को इस चुनाव में मिले पचास प्रतिशत वोट भी यही सत्य सुना रहे हैं। यह पहली बार था कि दो रुपये किलो चावल जैसी योजनाएं या फ्री फोन, फ्री लैपटॉप या सब कुछ मुफ्त मिलेगा जैसी योजनाएं छोड़कर जनता को मुख्यधारा में शामिल होने का अहसास दिलाया गया। घर बनाने के लिए सरकार ने कहा-भूमि तुम्हारी हो तो घर हम बनाएंगे और खर्चे में भी धन साझा करेंगे। ग्राम प्रधानों ने आगे बढ़कर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं अमल कराईं। राज्य सरकार की मशीनरी इन योजनाओं पर बारीक नजर रख रही थी। पैसा खाने-खिलाने का चक्कर था नहीं और बिचौलिए समाप्त कर दिए गए थे। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हमेशा एक मुद्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले दो वर्षों में अराजकता पर अंकुश लगाने में सफलता पाई है। कानून एवं व्यवस्था सुधरने के अतिरिक्त कई वर्ष पूर्व प्रस्तावित हुए फ्लाईओवर बने, हर मुख्य सड़क का चौड़ीकरण और शहरों का सौंदर्यकरण हुआ, बिजली आने लगी और ईमानदार व्यापारी के लिए व्यापार करना आसान हुआ है। अयोध्या में दीपावली पर्व का सुरुचिपूर्ण उत्सव हो या प्रयाग में कुंभ का अभूतपूर्व संयोजन, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक वैभव का वैश्विक प्रदर्शन सभी के मन को भा गया। वर्षों से सोया हुआ स्वाभिमान जागा और राष्ट्रभक्ति का मंत्र जन-जन तक फूंकने में सफल मोदी सरकार के प्रति आम जनता का भरोसा बढ़ा। 2014 और 2017 के चुनाव में भाजपा को खुले हाथों से विजयी बनाने वाले उत्तर प्रदेश ने इस बार फिर वही प्रदर्शन तिहरा दिया। कई दशकों तक जातिवाद और भ्रष्टाचार का दंश झेल चुके उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव नतीजों के जरिये देश को एक नया संदेश दिया है।

(लेखिका जानी-मानी लोक गायिका हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य

सदियों से धर्मग्रंथों का उद्घोष है कि सत्य को जीवन में धारण करके ही मनुष्य परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। सत्य एक भाव है जो निश्छलता, पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक है। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जो व्यक्ति सत्य के साथ जीवन जीता है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत एवं सजग रहता है, उसके मार्ग का बाधक बनना इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि सत्य के साथ तो स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा होता है। जो लोग सत्यनिष्ठ होते हैं, वे परमात्मा के प्यारे होते हैं। कथन और आचरण दोनों का जब तक समन्वय नहीं होगा, सत्य का दर्शन दुर्लभ होगा। मन पहली बार ही अपनी आवाज सुनाकर सत्य और असत्य का भेद बताता है। इस राह में कठिनाइयां अनेक आती हैं, लेकिन जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, वे इन्हें भी पार कर ही जाते हैं। असत्य ज्यादा समय तक नहीं टिका रह सकता है।

यह देश सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का है, धर्मराज युधिष्ठिर का है। सत्य को अनुभूत किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा हृदय मंदिर पवित्र हो। आध्यात्मिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सत्य मात्र परमात्मा है, बाकी सारा संसार नश्वर है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होगा, उसकी यात्रा शून्य से महाशून्य की होगी। अंधकार से प्रकाश की तरफ होगी। अमृतत्व प्राप्ति की होगी। वह हमेशा असत्य को जीवन से निकालने का प्रयास करेगा। जो बुरे काम का बुरा नतीजा मानकर जीवन को जानते और समझते हैं, वे सदैव सत्य का अनुपालन करते हैं। सत्य चर्चा नहीं, चर्या का विषय है।

स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है कि सत्य का जीवन में अनुपालन करके मनुष्य असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि असत्य का कोई पैर नहीं होता है। अंततः सत्य ही विजयी होता है। दुनिया के सारे ताने-बाने और सपने झूठे हैं, मनुष्य को जिस दिन यह आध्यात्मिक बोध हो जाए, वह सत्य के करीब पहुंचता है। सत्य को जानना या समझना इतना आसान भी नहीं है। सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें, सत्य ही जीवन का आधार बन जाए। तब जाकर कहीं बात बनती है। तभी मनुष्य के अंदर देवत्व भी आता है। अनेक विधाओं और पूजा-पाठ की पद्धतियों को अपनाकर भी यदि जीवन में सत्य नहीं उतरा तो समझें सब निरर्थक है।

शंभू नाथ पांडेय

बेरोजगारी की बढ़ती समस्या

सुधीर कुमार

बढ़ती जनसंख्या और तद्नुसार रोजगार सृजन नहीं हो पाने से देश में बेरोजगारी का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता ही गया है

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक 6.1 फीसद रही। आंकड़ें के मुताबिक देश में 15 से 29 साल के युवा बेरोजगारी की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। शहरी युवाओं में बेरोजगारी की दर 7.8 फीसद, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 5.3 फीसद है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को लेकर विपक्ष जहां मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सरकार ने घटती विकास दर और बढ़ती बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कैबिनेट समितियों का गठन किया है।

हालांकि देश में सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, बेरोजगारी की समस्या सदैव बरकरार ही रही है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल भरा कार्य रहा है! दरअसल बढ़ती जनसंख्या और तद्नुसार रोजगार सृजन नहीं हो पाने से देश में बेरोजगारी दर का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता ही गया है। मौजूदा समय में भारत की गिनती दुनिया के सर्वाधिक बेरोजगार आबादी वाले देशों में की जाने लगी है। बेरोजगारी ऐसी आग है, जिसकी लौ में दिन-रात युवाओं को जलना पड़ रहा है। वहीं कई प्रतिभा संपन्न युवाओं का देश में सम्मान नहीं हो पाने के कारण उनका पलायन विदेशों की ओर हो रहा है!

आमतौर पर योग्यता के अनुसार काम न मिलने की दशा को बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न, खुली, चक्रीय, मौसमी और शिक्षित आदि बेरोजगारी के ही प्रकार हैं। इनमें शिक्षित बेरोजगारी राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक साबित होती है। बेरोजगारी की यह स्थिति भुक्तभोगी युवा के मन में सरकार के प्रति आक्रोश का भाव जगाती है। क्षमता एवं संभावना से परिपूर्ण युवा जब नौकरी के लिए बहाली की बाट जोहता है या फिर अपनी योग्यता से नीचे की नौकरी करने को लाचार होता है तो वह क्षुब्ध मन से काम करना प्रारंभ कर देता है। विडंबना यह है कि एक तरफ देश में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का दंश झेल रहे भुक्तभोगियों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप बेरोजगारी की गर्त में फंसे रहना उनकी विवशता हो गई है। इसी बेबसी की आड़ में कई युवा नकारात्मक मार्ग अख्तियार कर लेते हैं, जो एक खतरनाक स्थिति को जन्म देती है। विश्व के सबसे बड़े युवा राष्ट्र में शिक्षित और डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं की फौज भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह चिंतन करने का समय है कि कहीं हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में खोट तो नहीं! क्योंकि ऐसी शिक्षा ग्रहण करने से क्या फायदा, जो कल युवाओं को जीविकोपार्जन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर करे!

बहरहाल बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार को जहां ठोस नीति के जरिये बेकारी उन्मूलन और अवसरों के सृजन के प्रति संजीदा होना चाहिए, वहीं नौकरी के लिए केवल सरकार पर आश्रित न होकर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना युवाओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

हिंदी की अनिवार्यता

हिंदी के प्रति अनावश्यक दुराग्रह शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रोफेसर निरंजन कुमार ने नई शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर उठे विवाद को अनुचित एवं अनावश्यक ठहराया है। सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। ऐसे में हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाए तो भाषा के स्तर पर राष्ट्रीय एकता ही स्थापित होगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी होने के नाते उसे भी नई शिक्षा नीति में अहम स्थान मिलना ही चाहिए। भाषा में एकरूपता होने से राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिलती है। अब चूंकि युवा रोजगार, व्यापार, शिक्षा एवं पर्यटन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम होती है जो एक-दूसरे को जोड़ने में सहायक होती है। अतः पूरे देश में एक भाषा तो ऐसी होनी ही चाहिए जो लोगों को जोड़ने का कार्य करे और वह हिंदी से बेहतर कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। हिंदी की अनिवार्यता से किसी तरह की कोई विषमता नजर नहीं आती और इसलिए इसे राजनीतिक तूल देना उचित प्रतीत नहीं होता। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति देश को आगे ले जाने एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज, उत्तर प्रदेश

कल्पनाओं से परे है संघ

संघ से वैचारिक संघर्ष की अधूरी तैयारी शीर्षक से प्रकाशित अपने आलेख में लेखक बद्री नारायण ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरएसएस से मुकाबला करने के लिए जयहिंद वाहिनी और दूसरी बंग जननी वाहिनी के बनाए जाने का उल्लेख किया है। संघ के मुकाबले इस तरह के संगठन बनाने का एक मात्र मकसद पार्टी की खिसक रही राजनीतिक जमीन को सुदृढ़ करना है। यह किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अनिवार्य भी है। परंतु दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह दीदी की भी यही सोच है कि आरएसएस राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठनात्मक कार्य करता है। शायद देश की राजनीतिक पार्टियों की भी यह बहुत बड़ी भूल है। संघ का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं है। संघ का असली उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत कर राष्ट्र का संपूर्ण विकास करना है। विश्व का सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन 'संघ' लाठी डंडे व हिंसा के सहारे स्थापित नहीं हुआ है। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने संघ की स्थापना से पूर्व सैकड़ों वर्षों के इतिहास व भविष्य का गौरवशाली भारत का निर्माण कैसे हो, इसका गहन अध्यन व चिंतन किया तब जाकर संघ की स्थापना की थी। अपने देश को केवल संस्कृति, धर्म, परंपराओं के द्वारा ही देश के जन जन को एक साथ जोड़ा जा सकता है। संघ आज अपने उसी उद्देश्य में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे संगठन की कल्पना दीदी तो क्या विश्व में कहीं भी करना बहुत मुश्किल कार्य है।

sureshgoyal8@gmail.com

दो टूक जवाब

भारत हमेशा पड़ोसी देश का अपना फर्ज निभाता रहता है और बातचीत के लिए पाक को आमंत्रित भी करता है, लेकिन पाकिस्तान विश्वासघात की नाव पर हमेशा स